RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2019-2021 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com

www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

INDORE 24 MARCH TO 30 MARCH 2021 प्रति बुधवार वर्ष 06 अंक 31 पृष्ठ 8 कीमत 5 रु.

Inside News

अब दक्षिण अमेरिका के इस देश से कच्चा तेल खरीद रहा भारत Page 2

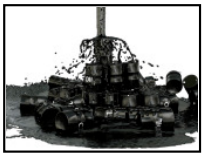

सरकार का फैसलाः 1 अप्रैल से बदल जाएगी सबकी सैलरी Page 5

कच्चा तेल ही नहीं खाद्य तेल भी लाते हैं 70 फीसदी विदेश से Page 7

editoria!

जल संरक्षण आवश्यक

सदियों पहले रहीम ने लिखा था- रहिमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून. दुनिया आज एक भयावह जल संकट के कगार पर खड़ी है और प्राकृतिक तौर पर उपलब्ध पानी को बचाने के अलावा इस संकट के समाधान का कोई दूसरा रास्ता नहीं है. लगभग सवा तीन अरब आबादी ऐसे खेतिहर इलाके में रहती है, जहां पानी की बड़ी किल्लत है. एक अनुमान के मुताबिक, साल 2040 तक 18 साल से कम आयु का हर चौथा बच्चा ऐसी जगहों पर रह रहा होगा, जहां पानी की बहुत अधिक कमी होगी. ऐसे बच्चों की तादाद करीब 60 करोड़ होगी. अगले एक दशक में 70 करोड़ लोग इस समस्या के कारण पलायन के लिए मजबूर होंगे. आज दुनिया की लगभग एक-तिहाई आबादी साल में कम-से-कम एक महीने गंभीर कमी का सामना करती है. भूजल के सबसे बड़े तंत्रों का एक-तिहाई हिस्सा मुश्किलों से घिर चुका है. हमारे देश में भी पानी की कमी की समस्या चिंताजनक स्थिति में है. स्वच्छ पेयजल तक आधी से अधिक आबादी की पहुंच नहीं है और हर साल लगभग दो लाख लोग इस वजह से मारे जाते हैं. नीति आयोग ने मौजूदा हालत को भारत के इतिहास का सबसे गंभीर जल संकट माना है. साल 2050 तक इस संकट के कारण सकल घरेलू उत्पादन के छह फीसदी मूल्य का नुकसान होगा. इन तमाम चुनौतियों के साथ घरों, शहरों, खेतों और उद्योगों की पानी से जुड़ी जरूरतें भी बढ़ती जा रही हैं. इस संदर्भ में हमें यह भी याद रखा जाना चाहिए कि भूजल के साथ-साथ नदियों और जलाशयों के प्रदूषण की स्थिति भी चिंताजनक होती जा रही है. केंद्र सरकार ग्रामीण और शहरी परिवारों को पेयजल मुहैया कराने की महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रही है. बारिश के पानी को संग्रहित करने के अलावा इस्तेमाल हो चुके पानी के शोधन पर भी जोर दिया जा रहा है. सिंचाई सुविधा के विस्तार के कार्यक्रम भी चल रहे हैं. इसके अलावा, खेती में कम पानी के उपयोग को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है, लेकिन इन पहलों में तेजी की दरकार है, क्योंकि समस्या बेहद गंभीर है. इसका अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि अगले एक दशक में हमारे देश में पानी की प्रति व्यक्ति वार्षिक उपलब्धता आज के 1588 घन मीटर की आधी रह जायेगी. आंकड़े बताते हैं कि हमारे जलाशयों में मानसून से पहले जून के महीने में पानी साल-दर-साल घटता जा रहा है. देश की जीवन रेखा कही जानेवाली गंगा, गोदावरी और कृष्णा जैसी बड़ी नदियां हाल के सालों में कई जगहों पर सूख गयी है. इनके अलावा भूजल के स्तर में गिरावट ने खतरे की घंटी बजा दी है. भारत में ग्रामीण क्षेत्र में 85 फीसदी, शहरों में 45 फीसदी और सिंचाई में 65 फीसदी पानी की आपूर्ति भूजल से ही होती है. जाहिर है कि चुनौतियां कम होने की जगह बढ़ रही हैं. ऐसे में पानी और पानी के स्रोतों के संरक्षण के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है.

कच्चे तेल पर टूटा कोरोना का कहर

15 दिनों में 15 फीसदी फिसला ब्रेंट क्रूड

मुंबई। एजेंसी

यूरोप में कोरोनावायरस के फिर से गहराते संकट की वजह से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की चाल सुस्त पड़ गई है. बीते सत्र में बेंचमार्क कच्चे तेल के दाम में 6.52 फीसदी की गिरावट आई है। वहीं ब्रेंट क्रूड करीब 6 हफ्ते बाद 60 डॉलर प्रति बैरल के करीब आ गया है और बीते 15 दिनों में कच्चे तेल का भाव 15 फीसदी से ज्यादा टूटा है।

कच्चे तेल के दाम में गिरावट आने से भारत में बीते 24 दिनों के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम में कटौती की गई है और जानकार बताते हैं कि दोनों वाहन ईंधनों के दाम में आगे और राहत मिल सकती है।

आईआईएफएल सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसीडेंट एनर्जी व करेंसी रिसर्च अनुज गुप्ता ने बताया कि कोरोना के फिर से गहराते प्रकोप के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की खपत पर असर पड़ने की आशंका बनी हुई है, लिहाजा, कीमतों पर आगे भी दबाव बना रह सकता है। हालांकि कच्चे तेल में नरमी रहने से भारतीय उपभोक्ताओं को आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीलज के दाम में और राहत मिल सकती है। यूरोप में तीसरी बार कोरोना का प्रकोप गहराने के बाद इसकी रोकथाम के लिए फिर से लॉकडाउन लगाए जाने के कारण बीते सत्र में कच्चे तेल के दाम में भारी गिरावट आई जिसके बाद ब्रेंट क्रूड का भाव करीब 6 सप्ताह के निचले स्तर पर आ गया है।

अंतरराष्ट्रीय वायदा बाजार इंटरकांटिनेंटल एक्सचेंज (ICE) पर ब्रेंट क्रूड (Brent Crude) के मई डिलीवरी अनुबंध में बुधवार को बीते सत्र से 0.10 फीसदी की नरमी के साथ 60.73 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार चल रहा था। बता दें कि 8 मार्च को ब्रेंट क्रूड का भाव 71.38 डॉलर प्रति बैरल तक उछला था जो कि इस साल का सबसे ऊंचा स्तर है। न्यूयॉर्क मर्कें टाइल एक्सचेंज (NYMEX) पर डब्ल्यूटीआई (WTI) के मई अनुबंध में बीते सत्र से 0.10 फीसदी की गिरावट के साथ 57.70 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार चल रहा था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल में आई नरमी के बाद देश में पेट्रोल और डीजल के दाम में 24 दिनों की स्थिरता के बाद तेल विपणन कंपनियों ने बुधवार को कटौती की है।

इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल के दाम घटकर क्रमशः 90.99 रुपये, 91.18 रुपये, 97.40 रुपये और 92.95 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं। डीजल की कीमतें भी दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में घटकर क्रमशः 81.30 रुपये, 84.18 रुपये, 88.42 रुपये और 86.29 रुपये प्रति लीटर हो गई हैं। पेट्रोल के दाम में दिल्ली में 18 पैसे, कोलकाता और मुंबई में 17 पैसे जबकि चेन्नई में 16 पैसे प्रति लीटर की कटौती की गई। वहीं, डीजल का भाव दिल्ली और कोलकाता में 17 पैसे जबकि मुंबई में 18 पैसे और चेन्नई में 16 पैसे प्रति लीटर कम हो गया है।

संभल जाएंः भारत के 18 राज्यों में मिला कोरोना का नया 'डबल म्यूटेंट' वैरिएंट

नई दिल्ली। एजेंसी

भारत में कोरोना वायरस एक बार फिर तेजी से पांव पसारता नजर आ रहा है। देश में पिछले 24 घंटे में 47,262 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। इसके साथ ही यहां कुल संक्रमित लोगों की संख्या एक करोड़ 17 लाख से अधिक हो गई है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी एक डराने वाली बात कही है। मंत्रालय ने बताया कि देश के 18 राज्यों में कोरोना वायरस का एक नया 'डबल म्यूटेंट' वैरिएंट मिला है। हालांकि मंत्रालय का यह भी कहना है कि अभी तक के आंकड़ों से यह स्पष्ट नहीं हुआ कि देश में कोरोना के बढ़ रहे संक्रमण और वायरस के नए वैरिएंट के बीच कोई संबंध भी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कोरोना का यह नया वैरिएंट कई अन्य देशों में भी मिल चुका है। दरअसल, पिछले कुछ समय से भारत समेत दुनियाभर में संक्रमण के मामले बढ़े हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, कोरोना के नए वैरिएंट के अभी पर्याप्त मामले नहीं मिले हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि यह वैरिएंट शरीर के इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा तंत्र से बचकर संक्रमण को बढ़ाता है। कोरोना वायरस का यह नया म्यूटेशन करीब 15 से 20 फीसदी नमूनों में पाया गया है और यह चिंता पैदा करने वाले पहले के वैरिएंट से मेल नहीं खाता। महाराष्ट्र से मिले नमूनों के विश्लेषण से पता चला है कि दिसंबर 2020 की तुलना में कोरोना के नमूनों में ई484क्यू और एल452आर म्यूटेशन के अंशों में बढ़ोतरी हुई है। अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के देश आने पर और अन्य कोरोना मरीजों से लिए गए नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग और इसके विश्लेषण से पता चला है कि फिलहाल इस वैरिएंट से संक्रमित लोगों की संख्या 10 है। (शेष पृष्ठ 2 पर)

प्रतिरक्षा तंत्र को चकमा देने में है सक्षम

पेट्रोल और डीजल पर केंद्र सरकार का कर संग्रह छह साल में 300 प्रतिशत से अधिक बढ़ा

नयी दिल्ली। एजेंसी

पेट्रोल और डीजल पर केंद्र सरकार का कर संग्रह पिछले छह साल में 300 प्रतिशत से अधिक हो गया। सरकार ने सोमवार को लोकसभा में यह जानकारी दी। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि केंद्र सरकार ने मोदी सरकार के आने के पहले साल में 2014-15 के दौरान पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क से 29,279 करोड़ रुपये और डीजल पर उत्पाद शुल्क से 42,881 करोड़ रुपये अर्जित किये।

अब दक्षिण अमेरिका के इस देश से कच्चा तेल खरीद रहा भारत

क्यों और कैसे चीन को लगेगा तगड़ा झटका

नई दिल्ली। एजेंसी

भारत ने पहली बार दक्षिणी अमेरिकी देश गुयाना से कच्चा तेल खरीदा है। इसकी पहली खेप 8 अप्रैल तक भारत पहुंचने की उम्मीद है। यह खेप गुजरात के मुंद्रा पोर्ट आएगी। भारत कच्चे तेल का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक है. गयाना, साउथ अमेरिका का वो देश है जहां पर सबसे ज्यादा भारतीय हैं।

उत्तर में अटलांटिक महासागर, दक्षिण में ब्राजील और पश्चिम में वेनेजुएला और पूर्व में सूरीनाम जैसे देशों से घिरे इसे 215,000 स्क्वॉयर किलोमीटर वाले देश पर चीन की भी नजरें हैं। साउथ अमेरिका का यह तीसरा सबसे छोटा द्वीप है और संसाधनों से भरपूर है। कहीं न कहीं तेल खरीद भारत की वो नीति हो सकती है जो चीन को घेरने में कामयाब हो सकती है।

क्यों गयाना से खरीदा जा रहा है तेल

केंद्र सरकार के सूत्रों की तरफ से बताया गया है कि कच्चे तेल के कार्गो को एचपीसीएल-मित्तल एनर्जी लिमिटेड द्वारा खरीदा गया है। एचपीसीएल-मित्तल एनर्जी कंपनी सरकारी तेल कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्प और स्टील किंग एलएन मित्तल का ज्वाइंट वेंचर है। एचएमईएल की पंजाब के बठिंडा में रिफाइनरी है। इस रिफाइनरी की क्रूड रिफाइनिंग की क्षमता 2.26 लाख बैरल रोजाना है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार ने तेल रिफाइनिंग कंपनियों से कहा है कि वे मध्य पूर्व के देशों से आयात घटाकर दूसरे क्रूड उत्पादक देशों से खरीद बढ़ाएं। ओपेक प्लस ने इसी महीने अप्रैल तक कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती जारी रखने का फैसला किया था। भारत सरकार सऊदी अरब समेत अन्य मध्य पूर्व देशों से कच्चे तेल की निर्भरता घटाने की कोशिश कर रही है। अप्रैल 2020 और जनवरी 2021 के बीच भारत के तेल आयात में ओपेक की हिस्सेदारी में बड़ी गिरावट आई है।

सऊदी अरब से तेल की खरीदारी में कमी

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी महीने में सऊदी अरब से कच्चे तेल की खरीदारी 36 फीसदी गिर गई है, जबकि अमेरिका से क्रूड आयात दोगुना से अधिक हो चुका है। समाचार एजेंसी रायटर्स के मुताबिक, इंडियन ऑयल ने मई में कच्चे तेल की खरीद 25 फीसदी घटाने की योजना बनाई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, भारत ओपेक प्लस से 86 फीसदी कच्चा तेल खरीदता है। इसमें से 19 फीसदी कच्चा तेल सऊदी अरब से खरीद जाता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी महीने में सऊदी अरब से कच्चे तेल की खरीदारी 36 फीसदी गिर गई है, जबकि अमेरिका से क्रूड आयात दोगुना से अधिक हो चुका है।समाचार एजेंसी के मुताबिक, इंडियन ऑयल ने मई में कच्चे तेल की खरीद 25 फीसदी घटाने की योजना बनाई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, भारत ओपेक प्लस से 86 फीसदी कच्चा तेल खरीदता है. इसमें से 19 फीसदी कच्चा तेल सऊदी अरब से खरीद जाता है।

गयाना में हैं 40 प्रतिशत भारतीय

गयाना, साउथ अमेरिका का वो देश है जहां पर सबसे ज्यादा भारतीय हैं। इस देश के राष्ट्रपति इरफान अली और उप-राष्ट्रपति भरत जगदेव दोनों ही भारतीय मूल के हैं। 2012 की जनगणना के अनुसार देश की 40 प्रतिशत आबादी भारतीय है और हिंदु धर्म दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। कई भारतीय ऐसे थे जो 19वीं सदी में देश में जाकर बस गए थे। यहां पर रहने वाले भारतीयों में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के हैं। हालांकि दक्षिण भारतीय लोगों की संख्या भी काफी ज्यादा है. ये भारतीय अपने-अपने तरीके से यहां की अर्थव्यवस्था में योगदान करते हैं।

क्यों लगने वाला है चीन को झटका

भले ही इस देश में भारतीयों की संख्या ज्यादा हो लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि पिछले कुछ दिनों से इस छोटे से देश पर चीन की नजरें हैं। सन् 1972 में चीन से टेक्निशियंस का एक छोटा सा ग्रुप इस देश में पहुंचा था। उसका मकसद एक प्रोजेक्ट को पूरा करना था। धीरे-धीरे चीन यहां पर अपने पैर जमाने लगा। साल 2015 में दुनिया की सबसे बड़ी तेल उत्पादक कंपनी एक्सॉन मोबिल को गयाना में तेल का बड़ा भंडार होने की खबरें मिली थीं। एक्सॉन अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री रेक्स टिलीरसन की कंपनी है।

चीन की एक योजना हुई फेल

एक्सॉन को देश में पांच बिलियन बैरल से ज्यादा का तेल मिला था। चीन, लैटिन अमेरिका में अपना प्रभाव जमाने की कोशिशों में लगा था और गयाना में तेल की खोज ने उसके लालच को बढ़ा दिया। माना गया कि यहां से चीन और गयाना के रिश्ते जटिल हो सकते हैं। हाल ही में चीन की तरफ से कोरोना वायरस वैक्सीन भी गयाना भेजे जाने की योजना बनाई गई। लेकिन मार्च में भारत की तरफ से कोविशील्ड की 80,000 डोज भेजकर उसकी योजना पर पानी फेर दिया गया था। फरवरी 2020 में गयाना ने कच्चे तेल का पहला कार्गो बेचा। कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ता गया. गयाना ने साल 2025 तक 750,000 बैरल तेल का उत्पादन एक दिन में करने का लक्ष्य तय किया है। इससे गयाना की अर्थव्यवस्था करीब तीन गुना तक बढ़ सकती है। निश्चित तौर पर भारत जो तेल गयाना से खरीद रहा है वो कहीं न कहीं चीन के लिए बड़ा झटका हो सकता है। अगर भारत एक परमानेंट बायर बनता है तो फिर यहां की अर्थव्यवस्था में उसका भारी योगदान होगा।

कोरोना प्रभावः सउदी अरब को तेल कंपनी अरामको से मिलने वाले कर में आई 30 प्रतिशत कमी

दुबई। एजेंसी

कोरोना वायरस महामारी के कारण अर्थव्यवस्था को हुये नुकसान का असर अरामको कंपनी के सरकार को किये जाने वाले कर भुगतान पर भी दिखाई दिया। वर्ष 2020 में सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको ने कर के रूप में सरकार को 30 प्रतिशत कम भुगतान किया है। सऊदी अरामको ने सोमवार को कहा कि देश की सबसे बड़ी करदाता कंपनी ने 2020 में 110 अरब डॉलर का भुगतान किया है जो एक साल पहले दिये गये 159 अरब डॉलर से 30 प्रतिशत कम है। सऊदी अरब ने 2021 के बजट में 263 अरब डॉलर के खर्च की योजना बनायी है। इस लिहाज से सऊदी अरामको के कर भुगतान के महत्व का पता चलता है। सार्वजनिक क्षेत्र की इस तेल कंपनी के कारोबारी आंकड़े इस राजशाही की वित्तीय स्थिति पर गहरा असर डालते हैं। सउदी अरब के कुल निर्यात में 80 प्रतिशत हिस्सा पेट्रोलियम का होता है वहीं उसके वित्तीय राजस्व में भी दो तिहाई योगदान इसी क्षेत्र से आता है। अरामको वर्ष के दौरान लाभांश के तौर पर 75 अरब डॉलर का भुगतान करने के अपने वादे पर कायम है। इसके बावजूद रॉयल्टी और आयकर भुगतान में कमी आधे से अधिक रही। कंपनी का लगभग सारा लाभांश सऊदी सरकार को मिलता है। कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी 98 प्रतिशत से अधिक है। सऊदी अरामको ने रविवार को कहा कि उसका लाभ 2020 में 44 प्रतिशत घटकर 49 अरब डॉलर रहा। इसका कारण कोरोना वायरस महामारी के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार में आया उठा-पटक रहा है।

भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह के लिये उपकरण की दूसरी खेप की आपूर्ति की

नयी दिल्ली। एजेंसी

केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि भारत ने ईरान में चाबहार बंदरगाह को उपकरण की दूसरी खेप की आपूर्ति की है। इससे पहले जनवरी में, भारत ने 2.5 करोड़ डॉलर से अधिक मूल्य के अनुबंध के तहत चाबहार बंदरगाह के लिये दो मोबाइल हार्बर क्रेन की खेप की आपूर्ति की थी। ऊर्जा के मामले में समृद्ध ईरान के दक्षिणी तट पर स्थित सिसतान-ब्लूचिस्तान प्रांत में इस बंदरगाह का विकास भारत, ईरान और अफगानिस्तान व्यापार संबंधों को मजबूती प्रदान करने के इरादे से कर रहे हैं। बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री मांडविया ने ट्विटर पर लिखा है, "चाबहार बंदरगाह विकसित करने की हमारी प्रतिबद्धता के साथ उपकरणों की दूसरी खेप शाहिद बेहस्ती टर्मिनल पहुंच गयी है।" पिछले महीने, बंदरगाह, जलमार्ग और पोत परिवहन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव संजय बंदोपाध्याय ने कहा था कि वेनिस के समीप बंदरगाह पर लदान के लिये दो और क्रेन खड़े हैं। ये क्रेन चाबहार बंदरगाह मार्च अंत तक पहुंच जाएंगे। उन्होंने कहा था कि दो और क्रेनों की जून अंत तक आपूर्ति की जाएगी। भारत और ईरान ने 23 मई, 2016 को कुल 8.5 करोड़ डॉलर के द्विपक्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किये गये थे। यह अनुबंध पहले चरण के तहत बंदरगाह पर उपकरण, मशीनीकरण और परिचालन शुरू करने को लेकर था। इस संदर्भ में विशेष उद्देश्यीय कंपनी...इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लि., मुंबई का गठन पोत परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत किया गया था। चाबहार बंदरगाह के विकास से भारत और ईरान के बीच आर्थिक रिश्तें प्रगाढ़ होंगे। साथ ही दोनों देशों के बीच समुद्री मार्ग से व्यापार को गति मिलेगी।

संभल जाएंः भारत के 18 राज्यों में मिला कोरोना का नया 'डबल म्यूटेंट' वैरिएंट

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

गृह मंत्रालय ने बीते मंगलवार को महामारी के प्रभावी नियंत्रण के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए थे, जो एक अप्रैल से 30 अप्रैल तक लागू रहेंगे। इस दिशा-निर्देश में देश के कुछ हिस्सों में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों को जांच, निगरानी और उपचार की प्रक्रिया को सख्ती से लागू करने का अधिकार दिया गया है। प्रत्येक व्यक्ति कोरोना से बचने के नियमों का पालन करे, उन्हें यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है। इसकी अलावा सभी पात्र लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया तेज करने को भी कहा गया है।

पेट्रोल और डीजल हो सकते हैं और सस्ते

जानिए क्यों मिल सकती है महंगे तेल से राहत

नई दिल्ली। एजेंसी

कोरोना वायरस का असर दुनिया भर में फिर से बढ़ने की आशंका के बाद कच्चे तेल की चाल सुस्त पड़ गई है। इसका असर भारत में भी देखने को मिला जहां काफी समय के बाद पहली बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की गई है। हालांकि बाजार के जानकार मान रहे हैं कि संकेत यही रहे तो ग्राहकों को पेट्रोल और डीजल में आगे भी राहत मिलेगी।

कितना टूटा है कच्चा तेल

ब्रेंट क्रूड फिलहाल 62 डॉलर प्रति बैरल के स्तर से नीचे कारोबार कर रहा है। बीते सत्र में कीमतें गिरावट के साथ 61 डॉलर से भी नीचे पहुंच गई थीं। इससे पहले 8 मार्च को ब्रेंट क्रूड का भाव 71.38 डॉलर प्रति बैरल तक उछला था जो कि इस साल का सबसे ऊंचा स्तर है। यानि बीते 15 दिनों में कच्चे तेल का भाव 15 फीसदी से ज्यादा टूटा है। वहीं करीब 6 हफ्ते के बाद कीमतें एक बार फिर 60 डॉलर प्रति बैरल के स्तर के पास पहुंची हैं।

क्या है बाजार के जानकारों की राय

आईआईएफएल सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसीडेंट एनर्जी व करेंसी रिसर्च अनुज गुप्ता ने बताया कि कोरोना के फिर से गहराते प्रकोप के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की खपत पर असर पड़ने की आशंका बनी हुई है, लिहाजा, कीमतों पर आगे भी दबाव बना रह सकता है। वहीं कच्चे तेल में नरमी रहने से भारतीय उपभोक्ताओं को आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम में और राहत मिल सकती है।

क्रूड कीमतों में गिरावट का मिला फायदा

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल में आई नरमी के बाद देश में पेट्रोल और डीजल के दाम में 24 दिनों की स्थिरता के बाद तेल मार्केटिंग कंपनियों ने बुधवार को कटौती की है। बुधवार को जारी नए रेट के मुताबिक डीजल 17 और पेट्रोल 18 पैसे सस्ता हुआ है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल के दाम घटकर क्रमशः 90.99 रुपये, 91.18 रुपये, 97.40 रुपये और 92.95 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं।

सार्वजनिक उपक्रमों से सरकार को मिला 30,369 करोड़ रुपये का लाभांश

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

सरकार को चालू वित्त वर्ष में अब तक सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों से 30,369 करोड़ रुपये का लाभांश प्राप्त हुआ है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी है। सरकार ने संशोधित बजट अनुमान में चालू वित्त वर्ष के संशोधित बजट अनुमान में केन्द्रीय उपक्रमों से लाभांश प्राप्ति को पहले के 65,746.96 करोड़ रुपये से घटाकर 34,717.25 करोड़ रुपये कर दिया। निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के सचिव तुहीन कांत पाडे ने एक ट्वीट में कहा, "केन्द्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों से चालू वित्त वर्ष में (22.03.2021) तक सरकार की लाभांश प्राप्ति 30,369 करोड़ रुपये रही है।" दीपम ने यह भी कहा है कि उसे बीईएमएल के लिये कई आवेदन प्राप्त हुये हैं। "बीईएमएल के लिये निजीकरण के लिये कई ने रुचि दिखाई है। इसके लिये सौदा अब दूसरे चरण पर पहुंच गया है।" सरकार ने पिछले साल बीईएमएल में 26 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने के लिये शुरुआती बोली लगाने की समय सीमा को 22 मार्च तक के लिये बढ़ा दिया था। सरकार ने इसके लिये सबसे पहले जनवरी में रुचि पत्र आमंत्रित किये थे। बीईएमएल में सरकार की 54.03 प्रतिशत हिस्सेदारी है। बीईएमएल कंपनी रक्षा, रेल, बिजली, खनन और ढांचागत क्षेत्र में कारोबार करती है। मौजूदा बाजार मूल्य पर कंपनी की 26 प्रतिशत हिस्सेदारी का दाम 1,000 करोड़ रुपये के करीब होगा।

सेंसेक्स में आई 871 अंकों की भारी गिरावट

निफ्टी फिसल कर पहुंचा 14550 अंक से भी नीचे

मुंबई। एजेंसी

वैश्विक बाजारों के नकारात्मक रुख के बीच बिकवाली का सिलसिला चलने से बुधवार को सेंसेक्स 871 अंक टूट गया। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 871.13 अंक या 1.74 प्रतिशत के नुकसान से 49,180.31 अंक पर बंद हुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 265.35 अंक या 1.79 प्रतिशत के नुकसान से 14,549.40 अंक पर आ गया। सेंसेक्स की कंपनियों में महिंद्रा एंड महिंद्रा का शेयर सबसे अधिक करीब चार प्रतिशत टूट गया। एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, आईटीसी और एनटीपीसी के शेयर भी नुकसान में रहे। इस रुख के उलट एशियन पेंट्स और पावरग्रिड के शेयरों में लाभ रहा।

6 साल में पेट्रोल-डीजल पर 307 फीसदी बढ़ गया टैक्स

रिलायंस सिक्योरिटीज के रणनीति-प्रमुख विनोद मोदी ने कहा, "वैश्विक बाजारों के कमजोर रुख तथा देश में कोरोना वायरस मामले बढ़ने से निवेशकों की चिंता से स्थानीय शेयर बाजारों में बड़ी गिरावट आई।" उन्होंने कहा कि इसके अलावा डॉलर सूचकांक में बढ़त से भी निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई।

अन्य एशियाई बाजारों में चीन का शंघाई कम्पोजिट, हांगकांग का हैंगसेंग, जापान का निक्की और सियोल का कॉस्पी दो प्रतिशत तक टूट गए। शुरुआती कारोबार में यूरोपीय बाजार भी नुकसान में थे। इस बीच, वैश्विक बेंचमार्क ब्रेंट कच्चा तेल 2.78 प्रतिशत की बढ़त के साथ 62.48 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।

ओएनजीसी की गैस का दाम मामूली बढने, रिलायंस- बीपी का कम होने के आसार

नयी दिल्ली। एजेंसी

सार्वजनिक क्षेत्र की ओएनजीसी जैसी कंपनियों के लिये सरकार नियंत्रित प्राकृतिक गैस के दाम अगले सप्ताह होने वाली समीक्षा में मामूली बढ़कर 1.82 डालर तक होने की संभावना है। वहीं गहरे समुद्री क्षेत्र जैसे मुश्किल इलाकों से निकलने वाली गैस का दाम चार डालर प्रति दस लाख ब्रिटिश थर्मल यूनिट से कुछ नीचे आ सकता है।

सरकार हर छह माह में एक बार, पहली अप्रैल और पहली अक्टूबर को प्राकृतिक गैस के थोक भाव की समीक्षा करती है। बिजली, उर्वरक और सीएनजी/पीएनजी कंपनियां गैस की मुख्य ग्राहक हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी तेल एवं प्राकृतिक गैस कंपनी (ओएनजीसी) और आयल इंडिया लिमिटेड (आयल) जैसी कंपनी को आवंटित गैस क्षेत्रों से निकलने वाली गैस का दाम एक अप्रैल से 1.82 डालर प्रति दस लाख ब्रिटिश थर्मल यूनिट (एमएमबीटीयू) हो जायेगा। वर्तमान में यह दाम 1.79 डालर प्रति एमएमबीटीयू पर है। मामले की जानकारी रखने वाले दो लोगों ने यह जानकारी दी है।

वहीं गहरे समुद्री क्षेत्र जैसे मुश्किल इलाकों से निकलने वाली गैस का दाम मौजूदा 4.06 डालर से घटकर 4 डालर प्रति एमएमबीटीयू से नीचे जा सकते हैं।ओएनजीसी को क्षेत्र नामांकन आधार पर आवंटित किये गये जबकि रिलायंस इंडस्ट्रीज को ये क्षेत्र नई तेल खोज लाइसेंसिंग नीति (नेल्प) के तहत मिला था। तत्कालीन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार ने घरेलू परियोजनाओं की गैस का भाव तय करने का जो फार्मूला अपनाया था उसके तहत गैस के दाम ऊंचे जा हो सकते थे। वह फार्मूला वर्ष 2014 मेंलागू किया जाना था । उस साल चुनाव के बाद बनी भाजपा के नेतृत्व वाली राजग सरकार ने उस फार्मूले को अमान्य कर नया फार्मूला तय किया। इस फार्मूले के तहत अमेरिका (हेनरी हब), ब्रिटेन (नेशनल बैलेंसिंग प्वाइंट) , अलबर्टा (कनाडा) और रूस के बाजार की मात्रा के हिसाब से भारांकित वार्षिक कीमतों औसत के आधार पर एक तिमाही के अंतराल के साथ गैस मूल्य की समीक्षा की जाती है।

राज्य सभा के बाद अब लोकसभा में 'बीमा संशोधन विधेयक 2021' को मिली मंजूरी

नई दिल्ली। एजेंसी

संसद ने 'बीमा (संशोधन) विधेयक, 2021' को मंजूरी प्रदान कर दी, जिसमें बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा बढ़ा कर 74 फीसदी करने का प्रावधान किया गया है। लोकसभा में सोमवार को इस विधेयक को मंजूरी दी गई जबकि पिछले सप्ताह बृहस्पतिवार को राज्यसभा में विधेयक पारित हुआ था । निचले सदन में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ा कर 74 फीसदी करने से इस क्षेत्र की कंपनियों की बढ़ती पूंजी जरूरत को पूरा करने में मदद मिलेगी। सीतारमण ने कहा कि यह संशोधन इसलिए किया जा रहा है कि कंपनियां यह तय कर सकें कि उन्हें किस सीमा तक एफडीआई लेना है।

उन्होंने कहा कि बीमा क्षेत्र अत्यंत विनियमित क्षेत्र है जिसमें हर चीज, यहां तक कि निवेश से ले कर मार्केटिंग तक का विनिवेश होता है। उन्होंने कहा कि बीमा कंपनियां तरलता के दबाव का सामना कर रही हैं। उन्होंने कहा कि बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ा कर 74 फीसदी करने से इस क्षेत्र की कंपनियों की बढ़ती पूंजी जरूरत को पूरा करने में मदद मिलेगी। वित्त मंत्री ने कहा " बीमा क्षेत्र के नियामक ने सभी पक्षों के साथ गहन विचार विमर्श के बाद इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया।" मंत्री के जवाब के बाद लोकसभा ने 'बीमा (संशोधन) विधेयक, 2021' को मंजूरी दे दी । सीतारमण ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बेचे जाने के आरोप गलत हैं ओर वे ऐसे ही रहेंगे। बजट में घोषित नीति में इसका स्पष्ट उल्लेख है। उन्होंने विपक्ष के कुछ सदस्यों के

आरोपों को नकारते हुए कहा, "कोई हमारे पैसे को बाहर लेकर नहीं जाएगा, पैसा हमारे यहां ही रहेगा। और तो और मुनाफे का एक हिस्सा भी यहीं रहेगा।"

वित्त मंत्री ने कहा कि इस विधेयक का एलआईसी से कोई लेनादेना नहीं है। यह विधेयक बीमा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि जब बीमा क्षेत्र की बात की जाती है तो यह ध्यान देना चाहिए कि इसमें सार्वजनिक क्षेत्र की सात कंपनियां और निजी क्षेत्र से जुड़ी 61 कंपनियां हैं । मंत्री ने कहा, "जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तब बीमा कवर बढ़ना चाहिए । देश के दलितों, शोषितों, वंचित वर्गो सभी को सुविधा मिलनी चाहिए ।" उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इसी सोच के तहत जीवन ज्योति बीमा योजना पेश की थी। उन्होंने संप्रग के समय भाजपा द्वारा इस विधेयक का विरोध किये जाने की विपक्षी सदस्यों की टिप्पणी पर कहा, "तब हमारे नेताओं ने इसके विरोध में कदम लिया था जो तब की स्थिति के अनुसार था क्योंकि तब सुरक्षा मानक नहीं थे, लेकिन आज हम पर्याप्त सुरक्षा मानक लाये हैं।"

कांग्रेस के एक सदस्य की टिप्पणी का जवाब देते हुए सीतारमण ने कहा कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था लेकिन 'भ्रष्टाचार के राष्ट्रीयकरण का काम संप्रग के समय हुआ। उसे सुधारने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं।" उन्होंने कहा कि विपक्ष के सदस्यों ने नीरव मोदी आदि का नाम लिया, लेकिन उनका पालन-पोषण करने वाली कांग्रेस ही थी। सीतारमण ने कहा, "आप कांग्रेस को चलाने वाले अपने परिवार से पूछिए कि उन्होंने यह काम क्यों किया। " उन्होंने कहा कि 2015 में जब बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा बढ़ा कर 49 फीसदी की गई थी उसके बाद से 26,000 करोड़ का निवेश आया । उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा निवेश आने से न केवल प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी बल्कि लोगों को बेहतर पैकेज , बेहतर प्रीमियम की सुविधा मिल सकेगी तथा रोजगार भी बढ़ेंगे। सीतारमण ने कहा "इस विधेयक को गहन विचार विमर्श के बाद तैयार किया गया है और देश के हितों से कोई समझौता करने का सवाल ही नहीं उठता।"

News यू केन USE

आरबीआई ने बैंकों के लिये आवेदनों के आकलन को लेकर समिति गठित की

मुंबई। एजेंसी

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सोमवार को सार्वभौमिक बैंकों और लघु वित्त बैंकों के लिये आवेदनों के आकलन को लेकर आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर श्यामल गोपीनाथ की अध्यक्षता में स्थायी बाह्य परामर्शदात्री समिति (एसईएसी) के गठन की घोषणा की। आरबीआई ने अगस्त 2016 में सब प्रकार की (यूनिवर्सल) बैंक सेवाएं देने वाले बैंक के लिये सदा सुलभ लाइसेंस व्यवस्था और दिसंबर 2019 में लघु वित्त बैंक के सदा सुलभ लाइसेंस नीति को लेकर दिशानिर्देश जारी किये थे। इन दिशानिर्देशों में यह संकेत दिया गया था कि सार्वभौमिक बैंक और लघु वित्त बैंकों के आवेदनों की जांच शुरू में आरबीआई करेगा ताकि आवेदनकर्ताओं की पात्रता प्रथम दृष्टया तय की जा सके। इसमें यह भी कहा गया था कि एसईएसी में बैंक, वित्तीय क्षेत्र और अन्य संबंधित क्षेत्रों के चर्चित लोग होंगे। आरबीआई के बाद समिति आवेदनों का आकलन करेगी और एसईएसी का गठन की घोषणा केंद्रीय बैंक करेगा। आरबीआई ने केंद्रीय बैंक की पूर्व डिप्टी गवर्नर श्यामला गोपीनाथ की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति की घोषणा करते हुए कहा कि एसईएसी का कार्यकाल तीन साल का होगा। आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक रेवती अय्यर, आरबीआई के पूर्व कार्यकारी निदेशक और फिलहल एनपीसीआई (नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया) के चेयरमैन बी माहापात्र, केनरा बैंक के पूर्व चेयरमैन टी एन मनोहरन, पीएफआरडीए (पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण) के पूर्व चेयरमैन हेमंत जी कांट्रेक्टर इसके सदस्य हैं।

अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का निलंबन 30 अप्रैल तक बढ़ाया

एयर बबल के तहत ही उड़ेंगे विमान

नई दिल्ली। एजेंसी

उड्डयन नियामक नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने मंगलवार को कहा कि निर्धारित अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों का निलंबन 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। उड़ानें कोरोना वायरस के चलते निलंबित की गई थी। डीजीसीए ने कहा, "हालांकि, अंतरराष्ट्रीय तय उड़ानों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा चुनिंदा मार्गों पर एक-एक मामले के आधार पर अनुमति दी जा सकती है।" कोविड-19 महामारी के कारण 23 मार्च, 2020 से भारत में निर्धारित अंतरराष्ट्रीय यात्री सेवाएं निलंबित हैं। हालांकि विशेष अंतरराष्ट्रीय उड़ानें मई से वंदे भारत मिशन के तहत और जुलाई से चुनिंदा देशों के साथ द्विपक्षीय 'एयर बबल' व्यवस्था के तहत संचालित हो रही हैं। भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई, केन्या, भूटान और फ्रांस सहित 27 देशों के साथ 'एयर बबल' समझौता किया है। दो देशों के बीच इस 'एयर बबल' समझौते के तहत, विशेष अंतरराष्ट्रीय उड़ानें उनके क्षेत्र के बीच उनकी एयरलाइंस द्वारा संचालित की जा सकती है। डीजीसीए के परिपत्र ने यह भी कहा गया कि निलंबन अंतरराष्ट्रीय ऑल-कार्गो संचालन और इसके द्वारा अनुमोदित उड़ानों के संचालन को प्रभावित नहीं करता है।

कोविड-19 लॉकडाउन का एक साल: देश में अभी भी रोजगार का संकट

फरवरी 2021 में 6.9% रही बेरोजगारी दर

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

कोरोना वायरस महामारी पर काबू पाने के लिए पिछले साल 25 मार्च को लागू किए गए लॉकडाउन के चलते पैदा हुआ आजीविका का संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। एक साल बाद भी भारत बेरोजगारी की समस्या से उबर नहीं पाया है। सरकार ने महामारी के घातक प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया था, लेकिन इससे आर्थिक और वाणिज्यिक गतिविधियां थम गईं और बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार से हाथ धोना पड़ा। प्रवासी मजदूरों के पलायन ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया।

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) के आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2021 में बेरोजगारी की दर 6.9 प्रतिशत रही, जो पिछले साल इसी महीने में 7.8 प्रतिशत और मार्च 2020 में 8.8 प्रतिशत थी। आंकड़ों से पता चलता कि अप्रैल में बेरोजगारी दर 23.5 प्रतिशत तक पहुंच गई थी और मई में यह 21.7 प्रतिशत पर रही। हालांकि, इसके बाद थोड़ी राहत मिली और जून में यह 10.2 प्रतिशत और जुलाई में 7.4 प्रतिशत रही।

शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों में सुधार की जरूरत

सीएमआईई के आंकड़ों के मुताबिक, हालांकि बेरोजगारी की दर पिछले साल अगस्त में फिर बढ़कर 8.3 प्रतिशत और सितंबर में सुधार दर्शाते हुए 6.7 फीसदी हो गई। विशेषज्ञों के मुताबिक सीएमआईई के आंकड़ों में जुलाई के बाद से बेरोजगारी के परिदृश्य में सुधार के संकेत हैं, लेकिन इसमें स्थायित्व केवल विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में सुधार के बाद आएगा। रोजगार की दृष्टि से इस दौरान कृषि क्षेत्र का

प्रदर्शन अच्छा रहा लेकिन शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का 16.5 लाख लोगों ने उठाया फायदा

विशेषज्ञों ने कहा कि सरकार ने देश में नए सिरे से रोजगार पैदा करने के लिए कई कदम उठाए हैं लेकिन रोजगार के परिदृश्य में लगातार सुधार के लिए बार-बार नीतिगत हस्तक्षेप और जमीनी स्तर पर पहल की जरूरत है। श्रम मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार लगभग 16.5 लाख लोगों ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) से लाभ उठाया है। यह योजना अक्टूबर में शुरू की गई थी।

लॉकडाउन के दौरान रद्द हुए 99.95 प्रतिशत टिकटों के लिए धन वापसी की: इंडिगो

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

सस्ती विमानन सेवाएं मुहैया कराने वाली कंपनी इंडिगो ने बुधवार को कहा कि उसने लॉकडाउन के दौरान रद्द होने वाले 99.95 प्रतिशत टिकटों के लिए धन वापसी की है। कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप को रोकने के लिए पिछले साल 25 मार्च से लॉकडाउन लगाया गया था, जिसके चलते करीब दो महीने तक विमानन सेवाएं बंद रहीं। उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल सितंबर में सभी विमानन कंपनियों को निर्देश दिया था कि वे उन यात्रियों को पूरी धनराशि 31 मार्च 2021 तक वापस करें, जिनकी उड़ानें लॉकडाउन अवधि (25 मार्च 2020 से 24 मई 2020) के दौरान रद्द कर दी गई थीं। इंडिगो ने एक बयान में कहा, "मई 2020 में परिचालन फिर से शुरू होने के बाद इंडिगो उन ग्राहकों को तेजी से धन वापसी कर रहा है, जिनकी उड़ानें लॉकडाउन के दौरान रद्द कर दी गई थीं। विमानन कंपनी ने पहले ही 1,030 करोड़ रुपये के करीब धनराशि वापस की है, जो कुल बकाया राशि का लगभग 99.95 प्रतिशत है।"

सरकार का फैसला

1 अप्रैल से बदल जाएगी सबकी सैलरी

नई दिल्ली। एजेंसी

एक अप्रैल 2021 आने में बस कुछ ही दिन बचे है। आने वाला महीना आपके जेब पर सीधा असर डालने वाला है।सैलरी का नया नियम 1 अप्रैल से लागू होने जा रहा है। बता दें कि नई वेतन कोड के मुताबिक, आपको हर महीने मिलने वाली पूरी रकम में वेतन का हिस्सा 50% होना चाहिए। ध्यान रहे कि वेतन के दायरे में मूल वेतन, महंगाई भत्ता और प्रतिधारण भत्ता आता है। यानी, इन तीन को जोड़कर मिलने वाली कुल राशि महीने में मिलने वाली कुल रकम की आधी होनी चाहिए। शेष आधी राशि में अन्य भत्ते शामिल होंगे। लेकिन अगर यह राशि 50% से अधिक हो गई तो अतिरिक्त रकम वेतन का हिस्सा मान ली जाएगी।

जानें सैलरी में क्या है टैक्स फ्री आपके लिए ये जानना जरूरी है कि बेसिक सैलरी, स्पेशल अलाउंस, बोनस आदि पूरी तरह टैक्सेबल हैं। वहीं, फ्यूल और ट्रांसपोर्ट, फोन, अखबार और किताबों आदि के लिए मिल रहे भत्ते पूरी तरह टैक्स फ्री हैं। जबकि एचआरए की गणना का नियम है और उस नियम के तहत एचआरए पूरी तरह या फिर उसका कुछ हिस्सा टैक्स फ्री हो सकता है। वहीं, बेसिक सैलरी के 10% के बराबर एनपीएस कंट्रिब्यूशन भी टैक्स फ्री है, उससे अतिरिक्त रकम पर टैक्स देना होता है। वहीं, ग्रैच्युइटी के मद में 20 लाख रुपये तक की जमा रकम पर कोई टैक्स नहीं देना होता है। सैलरी स्ट्रक्चर के मुताबिक टेक होम सैलरी की बात करें तो यह 1.14 लाख रुपये यानी कुल सीटीसी का 76.1% जबकि पूरे 18 लाख के पैकेज पर टैक्स की बात करें तो यह 1.10 लाख रुपये या कुल एनुअल सीटीसी का 6.1% होता है। वहीं, आप साल में 1.96 लाख रुपये की बचत कर पाते हैं जो सीटीसी का 10.9% है।

फिलहाल टैक्स फ्री कितना हिस्सा समझने के लिए मंथली सीटीसी 1.5 लाख रुपये यानी सालाना पैकेज 18 लाख रुपये का है और आप सेक्शन 80C के तहत निवेश पर अधिकतम टैक्स 1.50 लाख रुपये की छूट प्राप्त करते हैं। अगर कंपनी ने आपको सेक्शन 80CCD(2) के तहत एनपीएस का भी लाभ दे रही है तो नियम के मुताबिक, बेसिक सैलरी का 10ज्ञ एनपीएस में जाता है और वह टैक्स फ्री होता है। मौजूदा सैलरी स्ट्रक्चर में बेसिक सैलरी सीटीसी का 32ज्ञ होती है। इस लिहाज से 1.50 लाख की मंथली सीटीसी में बेसिक सैलरी 48,000 रुपये होगी। फिर 50 प्रतिशत यानी 24,000 रुपये एचआरए तो एनपीएस में बेसिक (48,000 रुपये) का 10ज्ञ यानी, 4,800 रुपये जाएगा। चूंकि बेसिक सैलरी का 12% पीएफ में जाता है तो 5,760 रुपये हर महीने पीएफ में जाएंगे। इस तरह आपकी मंथली 1.50 लाख रुपये की सीटीसी में 82,560 रुपये हो गए।

नए स्ट्रक्चर से सैलरी में बढ़ेगा टैक्सेबल पार्ट एचआरए बेसिक सैलरी का प्राय 40 से 50% तक हुआ करता है। ऐसे में कुल मासिक रकम का यह 20 से 25% हिस्सा इसका ही हो जाएगा। अब अगर बेसिक सैलरी, डीए और आरए को मिलकार कुल मासिक रकम का 50ज्ञ होना अनिवार्य है और 20 से 25% एचआरए होगा तो इसका मतलब है कि कुल मासिक रकम में बाकी भत्तों एवं अन्य मदों में मिलने वाली रकम की हिस्सेदारी घटकर 25-30% रह जाएगी।

जानिए एचआरए पर टैक्स छूट का नियम आपको एचआरए पर टैक्स छूट का नियम के बारे में जरुर जानना चाहिए। - एचआरए के मद में मिल रही पूरी रकम - अगर आप महानगर में काम कर रहे हैं तो बेसिक सैलरी के 50ज्ञ जबकि महानगर में नहीं हैं तो बेसिक सैलरी के 40ज्ञ के बराबर की रकम - आप हर महीने जितना किराया दे रहे हैं, उसमें से बेसिक सैलरी का 10ज्ञ घटाकर इन तीनों में जो भी रकम सबसे कम है, उतनी रकम टैक्स फ्री हो जाती है। सैलरी स्ट्रक्चर के मुताबिक आपको एचआरए मद में सालाना 2.88 लाख रुपये मिल रहे हैं, लेकिन आप 2.42 लाख रुपये पर ही टैक्स छूट ले सकते हैं क्योंकि एचआरए कैलकुलेशन रूल की तीन शर्तों के मुताबिक आपको ज्यादा से ज्यादा इसी रकम पर छूट मिल सकती है। इसलिए कि मान लीजिए आप 25,000 रुपये मासिक मकान किराया दे रहे हैं तो आपका सालाना किराया 3 लाख रुपये होगा। नियम के मुताबिक, 3 लाख रुपये में बेसिक सैलरी का 10% यानी, 57,600 रुपये घटाना होगा जो बचकर 2,42,400 रुपये है। आपको इसी रकम पर टैक्स छूट मिलेगी।

नए सैलरी स्ट्रक्चर में मि?लेगा ये फायदा नए सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो अब 1.50 रुपये मंथली सीटीसी में बेसिक सैलरी 75,000 रुपये अनिवार्य रूप से रहेगी। इस लिहाज से एचआरए 37,500 रुपये (महानगरों के लिए), पीएफ 9,000 रुपये, एनपीएस 7,500 रुपये, फ्यूल एवं ट्रांसपोर्ट 10,000 रुपये, फोन 1,000 रुपये, अखबार और किताबें 1,000 रुपये, बोनस 5,400 रुपये और ग्रैच्युइटी 3,600 रुपये की होगी। ऐसे में आपका एचआरए पार्ट बढ़ गया। आपका मासिक किराया तो वही 25,000 रुपये ही होगा। एचआरए की कुल रकम बढ़ जाने के कारण टैक्स फ्री के अतिरिक्त रकम भी बढ़ेगी और इस तरह टैक्स भी बढ़ेगा।

अब इन चीजों के लिए आधार नहीं रहा अनिवार्य, सरकार ने बदले नियम

नई दिल्ली। एजेंसी

सरकार ने पेंशन लेने वाले बुजुर्गों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (Digital Life Certificate) पाने के संबंध में नए नियम अधिसूचित किए हैं। अब पेंशनरों के लिए डिजिटल तौर पर जीवन प्रमाण पत्र लेने के लिए आधार को स्वैच्छिक बना दिया गया है। सरकार ने बेहतर प्रशासन संचालन (सामाजिक कल्याण, इनोवेशन, ज्ञान) नियम 2020 के तहत अपनी त्वरित संदेश समाधान वाली ऐप 'संदेश' और सार्वजनिक कार्यालयों में हाजिरी लगाने के लिए आधार प्रमाणीकरण को स्वैच्छिक कर दिया है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा 18 मार्च को जारी अधिसूचना में कहा गया है, "जीवन प्रमाण के लिए आधार की प्रामाणिकता स्वैच्छिक आधार पर होगी और इसका इस्तेमाल करने वाले संगठनों को जीवन प्रमाणपत्र देने के लिए वैकल्पिक तरीके निकालने चाहिए। इस मामले में एनआईसी को आधार कानून 2016, आधार नियमन 2016 और कार्यालय ज्ञापन और यूआईडीएआई द्वारा समय-समय पर जारी सकुर्लर और दिशानिर्देशों का अनुपालन करना होगा।"

क्यों शुरू किया गया डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट

पेंशनरों के लिए जीवन प्रमाण पत्र की शुरुआत तब की गई, जब कई बुजुर्गों को पेंशन लेने के लिए अपनी जीवित होने की सत्यता के लिए लंबी यात्रा कर पेंशन वितरित करने वाली एजेंसी के समक्ष उपस्थित होना पड़ता था। या फिर वह जहां नौकरी करते रहे हैं वहां से उन्हें जीवन प्रमाणपत्र लाना होता था और उसे पेंशन वितरण एजेंसी के पास जमा कराना होता था। डिजिटल तरीके से जीवन प्रमाणपत्र जारी करने की सुविधा मिलने के बाद पेंशनरों को खुद लंबी यात्रा कर संबंधित संगठन अथवा एजेंसी के समक्ष उपस्थित होने की अनिवार्यता से निजात मिल गई।

पेंशनरों को ये हो रही थी दिक्कत

लेकिन कई पेंशनरों ने अब इस मामले में शिकायत की है कि आधार कार्ड नहीं होने की वजह से उन्हें पेंशन मिलने में कठिनाई उठानी पड़ रही है अथवा उनके अंगूठे का निशान मेल नहीं खा रहा है। इसके लिए कुछ सरकारी संगठनों ने जहां 2018 में वैकल्पिक रास्ता निकाला था, वहीं अब जारी अधिसूचना के जरिए आधार को डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जारी करने के लिए स्वैच्छिक बना दिया गया है।

विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों को राहत

नहीं देना होगा 2% का डिजिटल टैक्स लेकिन ये है शर्त

नई दिल्ली। एजेंसी

सरकार ने फैसला किया है कि विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों (Foreign E-Commerce Firms) की भारतीय शाखा के जरिए बेची गईं वस्तुओं, सेवाओं पर दो प्रतिशत का डिजिटल कर (Digital Tax) नहीं लगेगा, ताकि उन्हें बराबरी का मौका मुहैया कराया जा सके। वित्त विधेयक 2021 में संशोधन करके यह स्पष्ट किया गया है कि विदेशी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को दो प्रतिशत के डिजिटल कर का भुगतान नहीं करना पड़ेगा, यदि वे स्थाई रूप से यहां हैं या वे आयकर देते हैं। हालांकि, जो विदेशी कंपनी किसी तरह का कर नहीं देती हैं, उन्हें इसका भुगतान करना होगा। डिजिटल कर की शुरुआत अप्रैल 2020 में हुई थी। यह केवल ऐसी विदेशी कंपनियों पर लागू है, जिनकी वार्षिक आय दो करोड़ रुपये से अधिक है और जो भारतीय उपभोक्ताओं को वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन बिक्री करती हैं।

डिजिटल लेनदेन पर आगे भी रहेगा जोर

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में वित्त विधेयक 2021 पर बहस का जवाब देते हुए कहा, "सरकारी संशोधन के माध्यम से... मैं यह स्पष्ट करना चाहती हूं कि यह उपकर उन वस्तुओं पर लागू नहीं होता है, जो भारत के निवासियों के पास हैं।" उन्होंने कहा कि सरकार डिजिटल लेनदेन के पक्ष में है और इसे कमजोर करने के लिए कभी भी कुछ नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, "यह उपकर भारत में कर का भुगतान करने वाले भारतीय व्यवसायों के बीच बराबरी के मुकाबले के लिए लगाया गया है और यह उन विदेशी कंपनियों के लिए है जो भारत में व्यापार करती हैं लेकिन यहां कोई आयकर नहीं देती हैं।"

घर पर बनाएं हर्बल कलर

15 आसान तरीकों से होली पर ऑर्गेनिक कलर घर पर बनाएं

बाजारों में होली की धूम शुरू हो गई है। हालांकि कोरोना के कारण अलग-अलग ग्रुप बनाकर होली का त्योहार मना रहे हैं। लेकिन बदलते वक्त में हर्बल रंग की डिमांड अधिक बढ़ गई है। अधिकतर युवा वर्ग अपनी त्वचा को लेकर ज्यादा चिंतित रहते हैं, ऐसे में हर्बल कलर पहली पसंद बन रही है। आपको बता दें कि हर्बल कलर आप कई आसान तरीकों से घर पर भी बना सकते हैं और मजा ले सकते हैं। तो चलिए जानते हैं घर पर हर्बल कलर/नैचरल कलर/ऑर्गेनिक कलर बनाने की आसान विधि -

1. जासवंती के फूलों से आप कलर बना सकते हैं। फूलों को सूखाकर उसका पावडर बना लें और उसकी मात्रा बढ़ाने के लिए आटा मिक्स कर लीजिए। सिंदूरिया के बीज लाल रंग के होते हैं, इनसे आप सूखा व गीला लाल रंग बना सकते हैं।
2. लाल रंग बनाने के लिए सूखे लाल चंदन को आप गुलाल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। यह सुर्ख लाल रंग का पावडर होता है, इससे त्वचा संबंधी कोई बीमारी नहीं होती है।
3. लाल रंग को बनाने का एक और दूसरा तरीका भी है। दो छोटे चम्मच लाल चन्दन पावडर को पांच लीटर पानी में डालकर उबालें। इसमें बीस लीटर पानी और डालें। अनार के छिलकों को पानी में उबालकर भी लाल रंग बनाया जा सकता है।
4. बुरांश के फूलों की सहायता से भी लाल रंग बनाया जा सकता है। पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने वाले इन फूलों को रातभर पानी में भिगो कर रख दें। सुबह तक आपका लाल रंग तैयार हो जाएगा।
5. तटीय क्षेत्रों में पलिता, मदार और पांग्री के फूल पाए जाते हैं। इन फूलों को रातभर पानी में भिगो कर रख दें, सुबह तक आपका लाल रंग तैयार हो जाएगा।
6. मेहंदी को आपने अब तक गीली करके हाथों पर लगाया है। इसके सूखे पावडर को आप हरे रंग की तरह इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बेहतर होगा इस रंग को गीला नहीं करें..अन्यथा आपकी ड्रेस या अन्य जगह पर मेहंदी का कलर चढ़ जाएगा।
7. हरा रंग बनाने के लिए गुलमोहर की पत्तियों को सुखाकर, महीन पावडर कर बना लें। आपका हरा रंग तैयार है।
8. चुकंदर से नेचरल गहरा पिंक कलर बनाया जा सकता है। चुकंदर को किस लें और एक लीटर पानी में भिगों कर रख दें। सुबह तक आपका पिंक कलर तैयार हो जाएगा।
9. टेसू के फूलों की मदद से आप सुंदर-सा नारंगी रंग तैयार कर सकते हैं। टेसू के फूलों को रातभर पानी में भिगोकर रख दें, सुबह तक आपका नारंगी रंग तैयार हो जाएगा। कहते हैं कि कान्हा जी भी टेसू के फलों से ही होली खेलते थे।
10. हरसिंगार के फूलों से आप सुंदर सा नारंगी कलर बना सकते हैं। इसे भी आप को पानी में कुछ घंटों के लिए भिगोकर रखना होगा।
11. नारंगी रंग बनाने के लिए आप चंदन के पावडर का इस्?तेमाल कर सकते हैं। एक चुटकी चंदन के पावडर में एक लीटर पानी मिला दें।
12. अमलतास, गेंदा और पीले सेवंती के फूलों से भी नैचरल पीला रंग तैयार किया जा सकता है। फूलों की पत्तियों को सूखा कर उन्हें बारीक पीस लें।
13. एक चम्मच हल्दी को दो लीटर पानी में मिला लें, रंग गाढ़ा करने के लिए आप इसे उबाल भी सकते हैं। वहीं गेंदे के फूलों से ताजा पीला रंग तैयार किया जा सकता है। करीब 50 गेंदे के फूलों को 2 लीटर पानी में उबालकर रातभर भीगने दें। सुबह तक आपका कलर तैयार हो जाएगा।
14. जकरंदा के फूलों की पंखुडियों से आप नीला रंग तैयार कर सकते हैं। फूलों को सुखाकर बारीक पीस लें। यह फूल वैसे तो केरल में मिलता है लेकिन ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा।
15. जामुन को अभी तक खाया था, लेकिन उससे आप होली भी सकते हैं। जामुन को बारीक पीस लें और पानी मिला लें।

होली के 17 सरल और सस्ते उपाय

28 मार्च को होली की रात कोई एक जरूर आजमाएं

होली बहुत सारे उपाय आजमाए जाते हैं। यहां हम एक साथ कुछ सरल उपायों की सूची दे रहे हैं। उम्मीद है यह आपके काम आएंगे।

1. होलिका दहन के दिन अपने ऊपर से उतारा शरीर का उबटन होलिका में जलाने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं।
2. घर, दुकान और कार्यस्थल की नजर उतारकर उसे होलिका में दहन करने से लाभ होता है।
3. भय और कर्ज से निजात पाने के लिए नरसिंह स्तोत्र का पाठ करना लाभदायक होता है।
4. होलिका दहन के बाद जलती अग्नि में नारियल दहन करने से नौकरी की बाधाएं दूर होती हैं।
5. लगातार बीमारी से परेशान हैं, तो होलिका दहन के बाद बची राख मरीज के सोने वाले स्थान पर छिड़कने से लाभ मिलता है।
6. सफलता प्राप्ति के लिए होलिका दहन स्थल पर नारियल, पान तथा सुपारी भेंट करें।
7. गृह क्लेश से निजात पाने और सुख-शांति के लिए होलिका की अग्नि में जौ-आटा चढ़ाएं।
8. होलिका दहन के दूसरे दिन राख लेकर उसे लाल रुमाल में बांधकर पैसों के स्थान पर रखने से बेकार खर्च रुक जाते हैं।
9. दांपत्य जीवन में शांति के लिए होली की रात उत्तर दिशा में एक पाट पर सफेद कपड़ा बिछाकर उस पर मूंग, चने की दाल, चावल, गेहूं, मसूर, काले उड़द एवं तिल के ढेर पर नवग्रह यंत्र स्थापित करें। इसके बाद केसर का तिलक कर घी का दीपक जलाकर पूजन करें।

10. जल्द विवाह के लिए होली के दिन सुबह एक पान के पत्ते पर साबूत सुपारी और हल्दी की गांठ लेकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और बिना पलटे घर आ जाएं। अगले दिन भी यही प्रयोग करें।
11. बुरी नजर से बचाव के लिए गाय के गोबर में जौ, अरसी और कुश मिलाकर छोटा उपला बना कर इसे घर के मुख्य दरवाजे पर लटका दें।
12. होलिका दहन की रात तगर, काकजंघा, केसर को 'क्लीं कामदेवाय फट् स्वाहा' मंत्र से अभिमंत्रित कर होली के दिन इसे अबीर या गुलाल में मिलाकर किसी के सिर पर डालने से वह वश में हो जाता है।
13. होली की रात 'ॐ नमो धनदाय स्वाहा' मंत्र के जाप से धन में वृद्धि होती है।
14. 21 गोमती चक्र लेकर होलिका दहन की रात शिवलिंग पर चढ़ाने से व्यापार में लाभ होता है।
15. उधार की रकम वापस पाने के लिए होलिका दहन स्थल पर अनार की लकड़ी से उसका नाम लिखकर होलिका माता से अपने धन वापसी का निवेदन करते हुए उसके नाम पर हरा गुलाल छिड़कने से लाभ होगा।
16. होली की रात 12 बजे किसी पीपल वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाने और सात परिक्रमा करने से सारी बाधाएं दूर होती हैं।
17. गोमती चक्र, कौड़ियां और बताशे जलती होली में स्वयं पर से उतार कर डालने से भी जीवन की हर बाधा स्वाहा हो जाती है।

इस साल राशि के अनुसार ऐसे करें होलिका दहन पूजा

फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होलिका दहन किया जाता है। इस साल होलिका दहन के दिन अभिजीत मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र में इन योग को बेहद शुभ बताया गया है। ज्योतिषाचार्यों की मानें तो होलिका दहन शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। भद्रा व राहुकाल के दौरान पूजा-अर्चना करने की मनाही होती है। शुभ योग में होली पूजा करने से जीवन में सुख, शांति के साथ समृद्धि पाने की कामना पूरी होती है।

राशि के अनुसार करें होलिका की पूजा-
मेष और वृश्चिक राशि के लोग गुड़ की आहुति दें।
वृष राशि वाले चीनी की आहुति दें।
मिथुन और कन्या राशि के लोग कपूर की आहुति दें।
कर्क के लोग लोहबान की आहुति दें।
सिंह राशि के लोग गुड़ की आहुति दें।

तुला राशि वाले कपूर की आहुति दें।
धनु और मीन के लोग जौ और चना की आहुति दें।
मकर व कुंभ वाले तिल को होलिका दहन में डालें।
होलिका दहन के दिन बन रहे ये अशुभ मुहूर्त-

राहुकाल - 5:06 PM – 6:37 PM
यम गण्ड - 12:32 PM – 2:03 PM
कुलिक - 3:34 PM – 5:06 PM
दुर्मुहूर्त - 04:59 PM – 05:48 PM
वर्ज्यम् - 01:06 AM – 02:32 AM

होलिका दहन 2021 का समय

हिंदू पंचांग के अनुसार, 28 मार्च को होलिका दहन का शुभ मुहूर्त शाम 6 बजकर 37 मिनट से रात्रि 8 बजकर 56 मिनट तक रहेगा। इसके अगले दिन रंगों वाली होली खेली जाएगी।

होली पर रंग खेलने से पहले जानिए रंगों का मन पर कैसा होता है असर

होली रंगों का त्योहार है, और रंगों से ही इसका असली मजा है। रंगों का इस्तेमाल केवल मस्ती या मजे के लिए ही नहीं किया जाता, बल्कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के साथ ही धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से भी इन रंगों का विशेष महत्व है। जानिए इन रंगों का महत्व -

1 लाल रंग - लाल रंग ऊर्जा, साहस, महत्वाकांक्षा, क्रोध, उत्तेजना, उत्साह और पराक्रम का प्रतीक है। वहीं इस रंग को प्रेम और कामुकता का प्रतीक भी माना जाता है। लाल रंग द्वारा रक्त व हृदय संबंधी समस्याओं और मानसिक क्षीणता, आत्मविश्वास की कमी जैसी समस्याओं को हल किया जाता है। वहीं धार्मिक दृष्टि से भी लाल रंग का अत्यधिक महत्व है। देवी साधना में यह बेहद महत्वपूर्ण है।

2 सफेद - सफेद रंग शांति और शुद्धता का प्रतीक है। यह अशांत मन को शांति प्रदान करता है, विद्या प्राप्ति में सहायता करता है और जीवन में सकारात्मकता का संचार कर मन और

मस्तिष्क में सात्विकता प्रदान कर शुद्ध करता है। अत्यधिक क्रोधी स्वभाव के लोगों के लिए यह रंग बेहद सकारात्मक है।

3 हरा - हरा रंग शीतलता, ताजगी, हरियाली, सकारात्मकता, अपरिवर्तनशीलता, गौरव, प्रसन्नता का प्रतीक है। यह तनाव दूर कर, नाड़ी संबंधी रोगों, लिवर, आंत के रोगों एवं रक्त शोधन के लिए महत्वपूर्ण है। यह आत्मविश्वास, प्रसन्नता और शीतलता प्रदान करता है। इसे बुद्धि का रंग भी कहा जाता है। हरा रंग सौभाग्य और समृद्धि का भी सूचक है।

4 नीला - नीला रंग प्रेम, कोमलता, विश्वास, स्नेह, वीरता, पौरुषता को दर्शाता है। यह रक्तचाप, सांस संबंधी रोगों व आंखों के लिए फायदेमंद होता है। धार्मिक और ज्योतिष की दृष्टि से भी इस रंग का काफी महत्व है। हल्का नीला यानि आसमानी रंग शरीर में जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है और आध्यात्मिक विकास को दर्शाता है।

5 पीला - पीला रंग आरोग्य, शांति, सुकून, योग्यता, ऐश्वर्य और यश को दर्शाता है, वहीं हल्का पीला रंग बीमारी का सूचक है। पित्त व पाचन संबंधी समस्याओं में यह लाभकारी है। पीला रंग युवावस्था को भी दर्शाता है। यह बौद्धिक विकास को भी दर्शाता है और खुशी का अनुभव कराता है। पीला रंग स्पष्टवादिता का भी प्रतीक है।

कच्चा तेल ही नहीं खाद्य तेल भी लाते हैं 70 फीसदी विदेश से

नई दिल्ली। एजेंसी

पिछले कुछ ही महीने में खाद्य तेलों (Edible Oil) के दाम में करीब 30 फीसदी का उछाल आया है। इसकी कीमतों में बढ़ोतरी का मुख्य कारण है विदेशों में पामोलीन (Pemoline) के दाम में तीव्र उछाल। आखिर घरेलू बाजारों में खाद्य तेलों की कीमतों में बढ़ोतरी क्यों नहीं हो। इस समय हम अपनी जरूरत का करीब 70 फीसदी खाद्य तेल तो विदेश से मंगाते हैं। ऐसे में तेल उद्योग एवं कारोबार के केन्द्रीय संगठन- सीओओआईटी (COOIT- सेंट्रल ऑर्गेनाइज़ेशन फॉर ऑयल इंडस्ट्री एण्ड ट्रेड) ने ने सरकार को जेनेटिकली मॉडीफाइड ऑयलसीड (Genetically Modifide Oilseed) को बढ़ावा देने की मांग की है। आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से।

विदेशों पर है निर्भरता

इस सयम देश में करीब 23 मिलियन टन खाद्य तेल की हर साल जरूरत पड़ती है। इसमें से हम महज 8 मिलियन टन खाद्य तेल ही पैदा कर पाते हैं। यही वजह है कि हमें हर साल 15 मिलियन टन इडिबल ऑयल का इंपोर्ट (Edible Oil Import) करना होता है। इसके लिए हम करीब 10 अरब डॉलर खर्च करते हैं। यदि देश में ही तिलहनी फसलों को बढ़ावा दिया जाए तो इस मद में खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा का बचत हो सकता है।

जेनेटिकली मॉडीफाइड ऑयलसीड को देना होगा बढ़ावा

तेल उद्योग एवं कारोबार के केन्द्रीय संगठन- सीओओआईटी (COOIT- सेंट्रल ऑर्गेनाइज़ेशन फॉर ऑयल इंडस्ट्री एण्ड ट्रेड) का कहना है कि इस समय घरेलू

स्रोतों से तिलहनी फसलों की उपलब्धता पर्याप्त नहीं है। तिलहनी फसलों में भी खाद्य तेल वाली फसलें, जैसे सरसों, सोयाबीन, मूंगफली, नारियल, कपास बीज, तिल आदि का रकबा लगातार घटता जा रहा है। इसलिए सरकार को देश में जेनेटिकली मॉडीफाईड ऑयलसीड की खेती को बढ़ावा देना चाहिए।

आत्मनिर्भर भारत तभी बनेगा

COOIT का कहना है कि गेहूं या धान उगाने में हम भले ही आत्मनिर्भर हो गए हों, लेकिन खाद्य तेलों (Edible Oil) के मामले में हम बहुत पीछे हैं। यदि देश को ज़रूरी खाद्य क्षेत्र में 'आत्मनिर्भर' बनाना चाहते हैं तो ऑयलसीड का उत्पादन (Oilseed Production) हर हाल में बढ़ाना होगा। इसके लिए यह भी जरूरी है कि इन फसलों की खेती करने वाले किसानों के उत्पादों के मद्देनज़र उनके हितों को सुरक्षित रखा जाए।

आजादी से पहले हम करते थे निर्यात

आजादी से पहले भारत खाद्य तेलों का निर्यातक था। 1970 के दशक के शुरूआती वर्षों तक हम करीब करीब आत्मनिर्भर थे। फिर इसकी खपत तेजी से बढ़ने लगी। तब भी वर्ष 1994-95 के दौरान खाद्य तेलों के मामले में भारत की आयात पर निर्भरता मात्र 10 फीसदी की थी। अब बढ़ती आबादी एवं बेहतर होती जीवनशैली के चलते मांग बढ़ने तथा कम उत्पादकता के कारण बढ़ कर 70 फीसदी हो गई है।

बढ़ रही है प्रति व्यक्ति खपत

अपने यहां पारंपरिक रूप से खाने में तेल का कम उपयोग होता था। 1971 में यह पांच किलो प्रति वर्ष था। फिर 1972 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध तथा उसके बाद पड़े भयंकर सूखे की वजह से 1973 में खाद्य तेलों का प्रति व्यक्ति सालाना खपत महज 3.9 किलो प्रति व्यक्ति तक आ गया था। लेकिन उसक बाद इसमें धीरे धीरे बढ़ोतरी होती गई। यह वर्ष 2012-13 में 15.8 किलोग्राम हो गया। अभी यह 19.5 किलो प्रति व्यक्ति तक पहुंच गया है।

जीएसटी घटाने से मिलेगी तत्काल राहत

सीओओआईटी (COOIT) के चेयरमैन बाबू लाल डाटा का कहना है कि अगर स्वदेशी उत्पादकता (Domestic Productivity) और उत्पादन (Production) बहुत अधिक नहीं बढ़ते, तो हमारी आयातित तेलों पर निर्भरता बढ़ती चली जाएगी। ऐसे में महंगाई खूब बढ़ेगी। ऐसे में लोगों को तुरंत राहत पहुंचाने के लिए सरकार को खाद्य तेलों पर से 5 फीसदी जीएसटी हटाने पर विचार करना चाहिए।

Air Travel:

हवाई किराए के बाद अब एविएशन सिक्योरिटी फीस में इजाफा

1 अप्रैल से चुकाने होंगे इतने रुपये ज्यादा

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

हवाई सफर (Air Travel) के लिए किराए में बढ़ोतरी के बाद अब एविएशन सिक्योरिटी फीस (ASF, विमानन सुरक्षा शुल्क) भी बढ़ने वाली है। ए का भुगतान यात्रियों द्वारा किया जाता है। 1 अप्रैल से घरेलू यात्रियों के लिए एविएशन सिक्योरिटी फीस 200 रुपये होगी, जो अभी 160 रुपये है। वहीं अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए यह फीस 12 डॉलर हो जाएगी, जो अभी 5.2 डॉलर है। एविएशन सिक्योरिटी फीस की नई दरें 1 अप्रैल 2021 से जारी होने वाली टिकटों पर लागू होंगी। हाल ही में सरकार ने डॉमेस्टिक हवाई किराए की लोअर लिमिट 5 फीसदी बढ़ाने का फैसला किया है। इसकी वजह एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी एटीएफ की बढ़ रही कीमतें हैं। हवाई किराए की अपर लिमिट फिलहाल मौजूदा स्तर पर ही रहेगी। इससे पहले फरवरी में सरकार ने हवाई किराए के प्राइस बैंड को बढ़ाने का फैसला किया था। उस समय मिनिमम किराए में 10 फीसदी और मैक्सिमम किराए में 30 फीसदी का इजाफा किया गया था। अब ASF भी बढ़ने से हवाई सफर करना और महंगा होने वाला है।

इससे पहले 1 सितंबर 2020 को बढ़ी थी ASF

इससे पहले सरकार ने एक सितंबर 2020 से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय विमान यात्रियों के लिए ASF को बढ़ाया था। पिछले साल सितंबर में घरेलू हवाई यात्रियों के लिए ए को 150 रुपये से बढ़ाकर 160 रुपये और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए 4.85 डॉलर से बढ़ाकर 5.2 डॉलर किया गया था। विमानन कंपनियां टिकट की बुकिंग के वक्त ए वसूल कर सरकार को जमा कराती हैं। इस राशि का इस्तेमाल पूरे देश के हवाईअड्डों की सुरक्षा व्यवस्था पर किया जाता है।

इन यात्रियों को ASF से है छूट

हालांकि यात्रियों की चुनिंदा कैटेगरी को इस फीस के भुगतान से छूट है। इनमें 2 साल से कम उम्र के बच्चे, डिप्लोमैटिक पासपोर्ट धारक, ऑन ड्यूटी एयरलाइन क्रू और एक ही टिकट के जरिए पहली फ्लाइट के 24 घंटों के अंदर दूसरी कनेक्टिंग फ्लाइट लेने वाले ट्रांजिट यात्री शामिल हैं।

अप्रैल अंत तक लागू रहेगी हवाई किराए की लोअर व अपर लिमिट

हवाई किराए के लिए सेट की गई लोअर और अपर लिमिट अप्रैल अंत तक लागू रहेगी। सरकार ने मई 2020 में घरेलू हवाई सफर (Domestic Air Travel) के किराए के लिए लोअर और अपर लिमिट को सेट किया था। और इसे 7 कैटेगरी में बांटा था। ये कैटेगरी फ्लाइट की ड्यूरेशन के आधार पर तय की गई थीं। पहली कैटेगरी 40 मिनट से कम ड्यूरेशन के हवाई सफर की, दूसरी कैटेगरी 40-60 मिनट के सफर, तीसरी कैटेगरी 60-90 मिनट के सफर, चौथी कैटेगरी 90-120 मिनट के सफर, पांचवीं कैटेगरी 120-150 मिनट के सफर, छठी कैटेगरी 150-180 मिनट के सफर और सातवीं कैटेगरी 180-210 मिनट के सफर की है।

आडी ने एस5 स्पोर्टबैक के नये संस्करण को 79.06 लाख में पेश

मुंबई। जर्मनी की प्रीमियम कार निर्माता ऑडी ने सोमवार को घरेलू बाजार में अपनी 'मिड-स्पेक परफॉर्मेंस कार' एस 5 स्पोर्टबैक का उन्नत संस्करण 79.06 लाख रुपये (एक्स-शोरूम कीमत) की शुरुआती कीमत पर बाजार में पेश किया। कंपनी ने एक विज्ञप्ति में कहा, पांच सीटों और चार दरवाजों वाले इस स्पोर्ट्स कूपे को भारत में पूरी तरह से विनिर्मित इकाई के रूप में आयात किया गया है। कंपनी ने कहा कि ऑडी इंडिया ने टियर -2 और टियर -3 शहरों (मझोले और छोटे शहरों) से मांग में वृद्धि देखी है, जिसमें आगे चलकर कंपनी को और तेजी आने की उम्मीद है। ऑडी इंडिया के प्रमुख बलबीर सिंह ढिल्लन ने कहा, "टियर- 2 और टीयर3 शहरों में भी हमारी बिक्री बढ़ रही है और हम उम्मीद करते हैं कि साल के दौरान इसमें और बढ़ोतरी होगी।"

कोविड-19 का असर: रेलवे की यात्रियों से कमाई 70% घटी, माल ढुलाई से आमदनी में इजाफा

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

रेलवे को कोविड-19 महामारी की वजह से चालू वित्त वर्ष में यात्री भाड़े के मद में 38,017 करोड़ रुपये के राजस्व का घाटा हुआ। लेकिन श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों को चलाने से घाटे की कुछ क्षतिपूर्ति हुई। वहीं माल ढुलाई के इनोवेटिव तरीकों को अपनाने से रेलवे का इस मद में राजस्व पिछले साल के मुकाबले बढ़ा है। रेलवे ने नियमित यात्री रेलगाड़ियों का परिचालन अब तक नहीं शुरू किया है लेकिन अब उसका ध्यान माल ढुलाई से आने वाले राजस्व को कायम रखने पर है। रेलवे माल ढुलाई से होने वाली आय में 22 मार्च तक पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 1,868 करोड़ रुपये (करीब दो प्रतिशत) की वृद्धि करने में सफल रही। भले ही यह दो प्रतिशत की वृद्धि है लेकिन इससे कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन की समस्या से उबरने में काफी सहायता मिली है।रेलवे को यात्री मद से होने वाली आय की जहां तक बात है तो पिछले वित्तवर्ष (20019-20) में यह 53,525.57 करोड़ रुपये रही, जो चालू वित्त वर्ष (2020-21) में घटकर 15,507.68 करोड़ रह गई। यह पिछले साल के मुकाबले 71.03 प्रतिशत कम है। आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल 2020 से फरवरी 2021 के दौरान यात्री भाड़े से 12,409.49 करोड़ राजस्व प्राप्त हुआ, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह राशि 48,809.40 करोड़ रुपये थी। यात्रियों की आवाजाही के बावजूद रेलवे ने प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने की शुरुआत की। एक मई से 30 अगस्त के बीच रेलवे ने 4000 श्रमिक विशेष ट्रेनों का परिचालन किया और 23 राज्यों से करीब 63.15 लाख श्रमिकों को उनके गंतव्यों तक पहुंचाया।

निगम द्वारा प्लास्टिक रिसायकलिंग हेतु प्रोडयुसर रिस्पांसिबिलिटी आर्गेनाईजेशन (पीआरओ) को दिये प्रमाण पत्र

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

प्लास्टिक के कचरे के कुशल पंबंधन के लिये सरकार ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 अनुसूचित किया है। यह नियम संपूर्ण भारत में प्रत्येक प्लास्टिक उत्पाइक, उसके आयातक तथा ब्रांड मालिको पर लागु हो गया है, निगम द्वारा आज सीटी बस आफिस में 8 प्रोडयुसर रिस्पांसिबिलिटी आर्गेनाईजेशन पीआरओ जिनमें प्लास्टिक रिसायकल पीआरओ बंसल पोलीमर्स, सत्यमित्र सेल्स एंड टेडिंग कंपनी लिमिटेड, इनोप्लास्ट टेक्नोलॉजी, मुनस्टार इंटरप्राइजेस प्रायवेट लिमिटेड, कुबेर इकोसिस्टम प्रायवेट लिमिटेड, नेपरा इन्वायरमेंट सॉल्युएशन, रिसायकल वेस्ट, होसविन इंकनिरेशन को प्लास्टिक रिसायकलिंग करने के प्रमाण पत्र वितरित किये गये। इस अवसर पर कंसलटेंट श्री अशद वारसी, जनसंपर्क अधिकारी राजेन्द्र गैरोठिया, सहायक यंत्री सुश्री गजल खन्ना व अन्य उपस्थित थे।

इंदौर नगर पालिक निगम आयुक्त श्रीमति प्रतिभा पाल ने बताया कि पीआरओ द्वारा प्लास्टिक को रिसायकल करने से निकलने वाली क्रेडिट का जिन कंपनी को आवश्यकता होगी, उनको उपलब्ध कराया जावेगा, यह पीआरओ निगम व कंपनी के मध्य समन्वय का कार्य करेंगे। नगर निगम इंदौर के ट्रेचिंग ग्राउण्ड देवगुराडिया में प्लास्टिक रिकवरी प्लांट का निर्माण किया गया है, इसके साथ ही सुखे अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रो में प्लास्टिक कचरे को एकत्र और पुनः नवीनीकरण किया जाता है। निगम द्वारा पुननवीनीकरण प्लास्टिक की कुल मात्रा में से निर्दिष्ट महीने के लिये उपयुक्त मात्रा का यह प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है। पीआरओ के माध्यम से शहर से ज्यादा से ज्यादा प्लास्टिक को रिसायकल करना हमारा उददेश्य है ताकि ईको सिस्टम से प्लास्टिक को बाहर किया जा सके।

उत्पादक जिम्मेदार संगठन (पीआरओ) द्वारा सरकारी विभागो एवं नगरीय निकायो के समक्ष प्लास्टिक के उत्पादको का प्रतिनिधित्व करेंगे और उनकी कार्य योजना से इस हेतु प्राधिकृत अधिकारी को अवगत कराएगे। पीआरओ विस्तारित उत्पादक संगठन देयक की बैठक सुनिश्चित करेंगे तथा समय-समय पर प्लास्टिक के संग्रहण, छंटाई, पृथक्करण, पुनचक्रण या अन्य प्लास्टिक अपशिष्ठ प्रबंधन ऑपरेटसरो, कचरा संग्रहण केन्द्र के लिये कार्य करेंगे। इसके साथ ही किसी भी तरह की प्लास्टिक के निर्माता, उसके आयातक तथा ब्राण्ड स्वामी द्वारा उत्सर्जित प्लास्टिक अपशिष्ट के 40 प्रतिशत प्लास्टिक कचरे के निपटान के लिये प्लास्टिक अपशिष्ठ प्रबंधन नियम 2016 अनुसार उत्पादक जिम्मेदार संगठन पीआरओ द्वारा सेवाऐं ली जाना अनिवार्य है।

विदित हो कि इन सभी पीआरओ को प्लास्टिक डिस्पोजल के प्रमाण पत्र प्रदान किये गये है, इसके पूर्व भी निगम द्वारा पीआरओ को सम्मति पत्र जारी किये गये थे, इसके लिये सभी पीआरओ द्वारा रूपये 50 हजार प्रतिमाह जमा करवाना अनिवार्य था, जिसके लिय अभी प्रत्येक पीआरओ द्वारा राशि जमा कराई जा रही है, अभी तक तक निगम को 26 लाख से अधिक की आय प्राप्त हुई है, इसके फलस्वरूप निगम को सालाना 45 से 50 लाख की आय होने लगेगी।

आत्म निर्भर भारत की दिशा में बिजली कंपनी ने बढ़ाए कदम...

एनएबीएल मापदंडों के अनुसार तैयार की गई मीटर टेस्टिंग लेब

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिहं चौहान के निर्देशानुसार आत्म निर्भर भारत की दिशा में तत्परता दिखाते हुए बिजली कंपनी ने भी इंदौर व उज्जैन स्थित मीटर टेस्टिंग लेब को हाईटेक रूप में तैयार किया है। इन्हें नेशनल एक्रिडिएशन बोर्ड फार टेस्टिंग एंड कालिब्रेशन लेबोरेटरी (एनएबीएल) मापदंड से तैयार किया गया है। अप्रैल में इन्हें एनएबीएल प्रमाण-पत्र मिलने की उम्मीद है। मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री अमित तोमर ने बताया कि पोलोग्राउंड स्थित मीटर टेस्टिंग लेब को हाईटेक किया गया है। इस लेब में प्रतिदिन हाईटेक रूप से 1200 मीटरों की टेस्टिंग हो जाएगी। इसके लिए एनएबीएल मापदंडों के अनुरूप टेस्टिंग ट्रे लगाई गई है। टेस्टिंग रिपोर्ट भी पूरी तरह कम्प्यूटराइज्ड दी जाएगी। यहां मात्र 30 से 60 मिनट में मीटरों का परीक्षण किया जाएगा। उपभोक्तागण मीटर टेस्टिंग की इस गतिविधि का लाइव भी देख पाएंगे। इससे उपभोक्ता संतुष्टि का ग्राफ और बढ़ेगा। इंदौर के पोलोग्राउड स्थित मीटर टेस्टिंग लेब की तरह की 1200 मीटर प्रतिदिन क्षमता वाली मीटर टेस्टिंग लेब उज्जैन में भी तैयार की गई है। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की दोनों ही स्थानों की लेब पर लगभग एक करोड़ रूपए खर्च हुए है। इससे कंपनी परीक्षण मामले में आत्म निर्भरता प्राप्त करेगी, वहीं वर्षभर में कंपनी के अन्यत्र स्थानों पर हाईटेक टेस्टिंग पर खर्च होने वाली बड़ी रकम भी बचेगी। प्रबंध निदेशक श्री तोमर ने बताया कि दोनों ही लेब की कंपनी स्तर पर मानिटरिंग की जिम्मेदारी अतिरिक्त मुख्य अभियंता श्री आरएस खत्री एवं अधीक्षण अभियंता श्री अचल जैन को दी गई है।

नए प्रयास से ये होंगे फायदे

■ग्रामीण क्षेत्रों में मीटरीकरण कार्य में तेजी आएगी ■शहरी क्षेत्र में मीटर खराब होने पर तुरंत मिलेगी रिपोर्ट ■गुणवत्ता बढ़ने से उपकरण ज्यादा वक्त तक कार्य करेंगे। ■स्थानीय स्तर पर परीक्षण होने पर समय, राशि बचेगी।

फास्टैग संग्रह 100 करोड़ रुपये के पार

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

फास्टैग के माध्यम से औसत दैनिक टोल संग्रह 100 करोड़ रुपये तक पहुंच गया हैं। सोमवार को संसद को यह जानकारी दी गई। सरकार ने 15 फरवरी की मध्यरात्रि से फास्टैग्स को अनिवार्य कर दिया था। इसके बाद बिना फासटैग वाले वाहनों से देश भर में इलेक्ट्रॉनिक टोल प्लाजा पर दोगुना टोल वसूलने की व्यवस्था कर दी गई। सड़क परिवहन, राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने एक लिखित जवाब में राज्यसभा को बताया कि 16 मार्च 2021 को तीन करोड़ से अधिक फास्टैग जारी किए गए। फास्टैग के माध्यम से दैनिक शुल्क संग्रह एक मार्च 2021 से 16 मार्च 2021 तक 100 करोड़ रुपये से अधिक रहा है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने एक जनवरी, 2021 से केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन के माध्यम से सभी 'एम' (चार पहिये वाले यात्री वाहन) और 'एनद्ध (चार पहिये वाले माल ढुलाई) श्रेणी के मोटर वाहनों में फास्टैग को फिट करना अनिवार्य कर दिया है। मंत्री ने कहा कि डिजिटल मोड के माध्यम से शुल्क भुगतान को बढ़ावा देने के लिए, 'फी प्लाजा' से एक निर्बाध मार्ग प्रदान करने, पारदर्शिता बढ़ाने, प्रतीक्षा का समय घटाने और प्रदूषण कम करने के लिए, सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर शुल्क वसूली वाले सभी लेनों को 'शुल्क प्लाजा का फास्टैग लेन' घोषित किया है, जो 15 से 16 फरवरी, 2021 के मध्य रात्रि से प्रभावी है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर उपयोगकर्ता शुल्क राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों और संग्रह का निर्धारण) नियम, 2008 के अनुसार एकत्र किया जाता है।

जायडस कैडिला ने जेनेरिक कोविड-19 दवा के दाम घटाए

नयी दिल्ली। एजेंसी

जायडस कैडिला ने रेमडेसिवीर दवा के अपने जेनेरिक संस्करण की कीमतों में उल्लेखनीय कटौती करने की घोषणा की है। कंपनी ने कोविड-19 की दवा के जेनेरिक संस्करण का दाम घटाकर 899 रुपये प्रति शीशी (100 एमजी) कर दिया है। कंपनी ने अगस्त, 2019 में रेमडैक को देश में पेश किया था। उस समय इंजेक्शन के रूप में दी जाने वाली इस दवा की 100 एमजी की शीशी का दाम 2800 रुपये था। जायडस कैडिला ने बुधवार को बयान में कहा कि रेमडेसिवीर कोविड-19 के इलाज में एक महत्वपूर्ण दवा है। इस कदम से ऐसी मुश्किल के समय मरीजों को काफी मदद मिल सकेगी।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित । संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुनः प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।